भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1949

14 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

डाटा आधारित नीति

1949. श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और स्टेकहोल्डरों के उपयोगार्थ भारतीय शहरों के संबंध में अशोधित डाटा (रॉ-डाटा) एक ही मंच पर उपलब्ध करा रही है ताकि डाटा-आधारित नीति निर्माण में सहायता मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंततः सभी 3739 नगर निगमों का डाटा इस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) क्या उक्त पहल से मुक्त डाटा पर आधारित नए ढांचे के सृजन का अवसर भी प्राप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) द्वारा 2019 में डेटा स्मार्ट सिटीज कार्यनीति की शुरूआत डेटा-संचालित गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इस कार्यनीति ने 100 स्मार्ट शहरों में डेटा-संचालित नीतियों और कार्यान्वयन पर व्यापक कार्य को उत्प्रेरित करने में मदद की। 2022 में अर्बन आउट कम फ्रेमवर्क की शुरुआत ने एम्प्लिफाइ नामक पोर्टल – एसेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफार्म फॉर लिवेबल, इनक्लूसिव एंड फ्यूचर-रेडी अर्बन इंडिया का संक्षिप्त रूप, पर 200+ शहरों के लिए 400+ मापदंडों पर 14 क्षेत्रों में डेटा साझा करने को सक्षम बनाया।

इस पर उपलब्ध डेटा की मात्रा और विविधता के कारण, एम्प्लिफाइ शहरी डेटा आवश्यकताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहुंच बन गया है। एम्प्लिफाइ माप योग्य है और इसमें देश के सभी कस्बों और शहरों के डेटा का संग्राहक बनने की क्षमता है।

पोर्टल द्वारा नई रूपरेखाएँ बनाना संभव है। इसके द्वारा शहरों के बीच परस्पर तुलना की जा सकती है, किसी विशेष शहर के भीतर या कई शहरों में फैले विशिष्ट क्षेत्रों या संकेतकों के लिए विश्लेषण किया जा सकता है और यह विभिन्न शहरी परिणाम संकेतकों के बीच सहसंबंध की जांच करने में सक्षम बनाता है।

*****